प्रधानमंत्री- लाभार्थी वी.सी. संवाद से मुख्यमंत्री भी जुड़े

जयपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर उद्बोधन तथा लाभार्थी संवाद में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़,

- **राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया।**

आंध्रप्रदेश, मिज़ोरम, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों के उपस्थित लाभार्थियों से संवाद किया।

उल्लेखनीय है कि, राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7402 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है। कैम्प में 47 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच, 3.52 लाख किसान क्रेडिट कार्ड व लगभग 24.33 लाख आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 2.14 लाख व पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 1 लाख लोगों को जोड़कर तथा 4.27 लाख से अधिक महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों एवं कलाकारों को पुरस्कृत करने के साथ कुल 1.6 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति में राजस्थान का चौथा स्थान है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर उद्बोधन तथा लाभार्थी संवाद में शामिल हुए।

मध्य, पश्चिमोत्तर भारत में बारिश के आसार

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के अलग-अलग स्थानों पर अगले 24 घंटे में तूफान और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने के आसार हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को बताया कि, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने और शीत लहर में वृद्धि के आसार हैं। अगले तीन दिनों में तमिलनाडु में

- **मौसम विज्ञान विभाग ने ओलावृष्टि की आशंका भी जताई।**

और केरल में 24 घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

देश के उत्तरी हिस्सों में अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने के आसार नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ , दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

टी.टी. को मंत्री बनाने के बाद भी करणपुर में भाजपा की हार

श्रीगंगानगर, 8 जनवरी (कासं)। करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपिन्दर सिंह (रूबी) कुन्नर ने भाजपा प्रत्याशी और राज्यमंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को 11 हजार 283 वोटों के अंतर से हराया।

मतगणना स्थल पर सुबह आठ बजे टीटी समर्थकों ने चुनाव जीतने की औपचारिक प्रक्रिया के तहत जैसे ही ईवीएम से नतीजे देखे तो हैरान रह गए।

- **कांग्रेस प्रत्याशी रूबी कुन्नर को सहानुभूति का लाभ मिला।**

भाजपा प्रत्याशी टीटी को पहले राउंड में जब 724 वोटों की बढ़त मिली तो भाजपाईयों और टीटी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तब मतगणना स्थल पर काउटिंग एजेंटों ने जय श्रीराम के जयघोष लगा दिए। लेकिन यह खुशी अगले राउंड में उड़न छू हो गई। दूसरे राउंड में कांग्रेस के कुन्नर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीटी की बढ़त को रोकते हुए 184 वोटों की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद कुन्नर ने पीछे नहीं देखा और लगातार अपनी बढ़त बनाई रखी। अंत में परिणाम उनकी झोली में आया।

करणपुर सीट से कांग्रेस ने अपने विधायक गुरमीत कुन्नर को प्रत्याशी बनाया था। गुरमीत के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित हो गया था। गुरमीत कुन्नर के बेटे रूपिन्दर सिंह रूबी कुन्नर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति का कार्ड खेला। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को न केवल प्रत्याशी बनाया बल्कि मतदान से पहले राज्य में नवगठित भजनलाल शर्मा की सरकार में राज्यमंत्री तक बना दिया और भारी मतों से जीतने का दावा किया।

लेकिन सोमवार को हुई मतगणना में राज्य मंत्री टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे सारे समीकरण बदल दिए।

टी.टी. ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया

जयपुर, 8 जनवरी (का.सं.)। चुनाव में मिली पराजय के बाद मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टी.टी. ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार किया। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार में सुरेन्द्र पाल सिंह टी.टी को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था।

- **राज्यपाल कलराज मिश्र ने त्याग पत्र स्वीकार किया।**

108 फीट लंबी धूपबत्ती से महकेगा अयोध्या का राम मंदिर

आगरा, 08 जनवरी।,रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गुजरात से लायी जा रही 108 फिट लंबी धूपबत्ती श्रद्धालुओं के बीच आस्था की सुगंध में चार चांद लगायेगी।

राम मंदिर को महकाने के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या ले जाई जा रही है। भरतपुर से होते हुए अगरबत्ती आगरा के फतेहपुर सीकरी और किरावली पहुंची। इसके पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच गए और धूपबत्ती को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वडोदरा से शुरू हुआ सफर धूपबत्ती की शोभायात्रा में बदल गया है। 3610 किलो वजन की 108 फुट लंबी और करीब साढ़े तीन फीट चौड़ी धूपबत्ती को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने धूपबत्ती का फूल बरसा कर स्वागत किया।

आज कल के हालात...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सत्तारुढ़ दल इन राजनीतिक घटनाओं में मु.सचिव/सी.एम.ओ. से "इनपुट" की आशा करता है। आर.ए.एस./आई.ए.एस. अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग भी ऐसा एक विषय है। आम सरकारी अफसर, इन ट्रांसफर लिस्टों से सरकार की नीयत व नैतिकता व "फेयरनैस" को आंकता है, सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव इन "ट्रांसफर"की लिस्टों को लेकर आता है। जैसे अब यह खोज होगी कि, करणपुर में भाजपा प्रत्याशी को चुनाव से पूर्व मंत्री बनाने का निर्णय किसकी राय से हुआ। नाथद्वारा में भाजपा के विजयी उम्मीदवार, महाराणा परिवार के कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपनी जीत के बाद वहां के एस.डी.ओ. को चुनाव में तटस्थ भूमिका नहीं रखने के कारण बदलने की मांग की थी। ऐसी ही मांग राजेन्द्र राठौड़ ने तारानगर के निर्वाचन अधिकारी के बारे में की। एक अन्य विधायक, जो अब मंत्री भी हैं, ने भी स्थानीय चुनाव अधिकारी के बारे में ऐसी बात की थी, क्योंकि उक्त प्रशासनिक अधिकारी ने एक प्रदर्शन के दौरान लठ मारा था और अब वह अदिकारी "सलूट" मारे, यह अच्छा नहीं लगेगा। इन सभी ट्रांसफर की मांगों पर, एक बार तो अमल हुआ, फिर ऑर्डर रदद् कर दिये गये। निर्णय का कारण कुछ भी रहा हो: प्रशासनिक शिथिलता, राजनीतिक दबाव या पूर्ण जानकारी का अभाव। पर क्योंकि, लिस्ट मु.सचिव की थी, वह बेचारा व्यर्थ ही आलोचना का लक्ष्य हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि, लिस्ट बनाने में सी.एम.ओ. सक्रिय नहीं था।

मु. सचिव किस प्राथमिकता को ज्यादा महत्व दे, बड़े-बड़े प्रोजेक्टस को लाने और क्रियान्वित कराने पर या छोटी-मोटी ट्रांसफर पोस्टिंग पर, जिनका राजनीतिक महत्व भी कम नहीं, विशेषकर, जबकि राजस्थान में एक परम्परा सी पड़ गयी थी कि, मुख्य सचिव का रुतबा ट्रांसफर - पोस्टिंग से ही आंका जाता है।

बिलकीस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भेजने के आदेश दिए और कहा कि 15 अगस्त 2022 को आम माफी के जो आदेश पारित किए गए, गुजरात सरकार उसके लिए सक्षम नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ही दोषियों की माफी का निर्णय करने की अनुमति है क्योंकि यह केस महाराष्ट्र में चला और सजा भी वहीं सुनाई गई थी।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भूइयां की डिवीज़नल बैंच ने यह फैसला सुनाया। आम माफी के आदेश के खिलाफ बिलक़ीस बानो व अन्य ने नवम्बर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।

बैंच ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि इस केस के किसी एक दोषी ने तथ्यों को छिपाया और झूठे बयान देकर शीर्ष अदालत को गुमराह किया। कोर्ट ने कहा कि सजा माफी का आदेश रद्द होने के बाद जेल से बाहर रहने की अनुमति नहीं है।

दोषियों को निर्देश दिए गए कि वे दो सप्ताह के भीतर जेल प्रशासन को रिपोर्ट करें।

शिक्षक भर्ती 2016 के पुन: परिणाम से बाहर हुए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं राज्य लोक सेवा आयोग की याचिका खारिज की

जयपुर, 8 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 के पुन: परिणाम में बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व आरपीएससी की याचिका पर दिए।

अपील में कहा गया कि, शिक्षक भर्ती को लेकर 30 अगस्त, 2017 को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई थी। इसके बाद इस उत्तर कुंजी के आधार पर 20 अप्रैल, 2018, को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। बाद में हाईकोर्ट के आधार पर चार प्रश्नों के जवाब बदले गए। जिसके चलते नियुक्त हुए कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए। राज्य सरकार ने 27 सितंबर, 2018 को पुन: परिणाम के आधार पर इन अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त कर दी। इस आदेश को शीतल बोचल्या व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया। अपील में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि, पुन: परिणाम में मेरिट से बाहर होने के चलते अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। यदि इन्हें पद पर रखा गया तो विज्ञापन में बताए पदों से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी। इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। इस पर प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता आर.पी. सैनी ने कहा कि प्रथम उत्तर कुंजी आरपीएससी ने ही जारी की थी और उसके आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई। जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में पुन: परिणाम के आधार पर उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी की अपील को खारिज कर दिया है।

- **सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में जारी उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी।**
- **बाद में हाई कोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्नों के जवाब बदले गए और दो बार नतीजे घोषित हुए तो कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए और इनकी सेवा समाप्त कर दी गई।**
- **इन अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी तो हाई कोर्ट ने सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया था जिसे सरकार ने चुनौती दी थी।**

भारत की "नेबरहुड...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण जाना जाता है और उनके चुनाव अभियान का एक मुख्य मुद्दा इस द्वीपीय देश से भारतीय सैनिकों को हटाने को लेकर था।

हालांकि मालदीव ने पिछले कुछ वर्षों में यदा-कदा चीन के प्रति अपना झुकाव दर्शाया है, लेकिन भारत के साथ उसके रिश्ते कुल मिलाकर स्वरूप एवं सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं।

अस्सी के दशक में जब मालदीव में सैन्य तख्तापलट हुआ था, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर उसे विफल किया था और जब इस द्वीपीय राष्ट्र का "वॉटर फिल्टरेशन सिस्टम" ठप्प हो गया था तब भारत ने जहाजों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए पेयजल भेजकर मालदीव की मानवीय सहायता की थी। मालदीव एक ऐसा देश हैं जहां पिछले कई दशकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार सर्वाधिक रही है।

मालदीव की नई सरकार का भारत के खिलाफ अचानक से सामने आया आक्रामक रूख इन आशंकाओं को बल प्रदान करता है कि मुइज़्ज़ू सरकार अपनी नीति को चीन के पक्ष में ले जाने की प्रक्रिया में है।

मालदीव भारत के लक्षद्वीप से महज 820 किमी और भारत के केन्द्र से 2,000 किमी की दूरी पर है। इसलिए मालदीव में चीन की संभावित एंट्री भारत के लिए सामरिक व सुरक्षात्मक हिसाब से गंभीर चुनौतियां पेश करती हैं।

भारत द्वारा जतायी गईं कठोर आपत्तियों की प्रतिक्रिया में मालदीव सरकार ने मरियम शिउना व दो अन्य उपमंत्रियों को निलम्बित कर दिया है जबकि भारत की मांग है कि इनका निलम्बन नहीं बल्कि निष्कासन किया जाना चाहिए। भारत में मालदीव के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने सोमवार को तलब किया और उनके देश के तीन उपमंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने को लेकर उन्हें "रॉयट्स एक्ट" पढ़कर सुनाया गया।

बताया जाता है कि मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शहबीब ने यह कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मालदीव द्वारा खराब किया गया है और उनमें सुधार करने की जिम्मेवारी अब राष्ट्रपति मुहज़्ज़ू की है। अब यह देखना शेष है कि क्या मुहज़्ज़ू इन संबंधों को सुधारने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। फिलहाल वह चीन के दौरे पर हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका यह प्रथम चीन दौरा है।

पुरानी पेंशन योजना के लिए भूख हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारी

8 से 11 जनवरी तक सभी सरकारी व रेल कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सोमवार से चार दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी।

पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच की स्टीरिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सभी सरकारी रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राजधानी में जन्तर मन्तर पर तथा अपने-अपने विभागीय प्रशासनिक कार्यालयों, उत्पादन इकाईयों तथा यूनिटों के सामने सुबह नौ बजे से सांय पांच बजे से तक क्रमिक अनशन/भूख हड़ताल पर बैठ गये जिसमें रेलवे, रक्षा, शिक्षा एवं अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।

संयुक्त मंच के संयोजक एवं ऑल इंडिया रेल्वे फैडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने जन्तर मन्तर, नई दिल्ली पर क्रमिक भूख हडताल पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली केन्द्र एवं प्रदेश के उन सभी सरकारी कर्मचारियों एवं रेल कर्मचारियों का प्रमुख मुद्दा है, जो दिनांक एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आये हैं और पिछले वर्ष से ही सभी सरकारी कर्मचारी, एवं रेल कर्मचारी, जिनमें रक्षा, शिक्षक तथा सरकारी उत्पादन इकाईयों आदि भी शामिल हैं, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक जोरदार आंदोलन और प्रदर्शन करते आ रहे हैं। गत वर्ष 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली भी हुई थी। उन्होंने कहा कि, अब यह आंदोलन रूकने वाला नहीं है, यह भूख हड़ताल अगले चार दिन, 11 जनवरी तक चलेगी और इसमें भारी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के साथ अन्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और यह आंदोलन पूरे देश के साथ-साथ रेलवे के सभी प्रशासनिक कार्यालयों पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के झंडे तले आयोजित किया जा रहा है।

मिश्रा ने कहा कि, पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना कर्मचारियों के बुढापे में उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सरकार खुद तो पेंशन लेती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बुढापे की उनको कोई परवाह नहीं। सरकारी कर्मचारियों के इतने आंदोलनों के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है जिसके उपरान्त आम हड़ताल नोटिस देने से पूर्व पहले सरकार को चेताने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारी, रक्षा, शिक्षक एवं रेल कर्मचारी नई दिल्ली में आज सुबह से ही जन्तर मन्तर के अलावा अपने-अपने मुख्यालयों, कारखानों एवं यूनिटों पर इस कंपकंपाती ठंड में भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं और चार तीन तक चलने वाली इस भूख हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर काफी रोष है और वे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर काफी उग्र होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, कर्मचारियों ने सरकार को अब एक आखिरी मौका देने का काम किया है इसके बाद सीधे आम हड़ताल का नोटिस सरकार को दिया जायेगी।

- **पुरानी पेंशन योजना बहाली से युक्त मंच की बैठक में निर्णय लिया गया कि, यह कर्मचारियों की तरफ से सरकार को आखिरी मौका है, उसके बार सीधे आम अड़ताल की जाएगी।**

मालदीव के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विदेश मंत्रालय पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मालदीव सरकार ने विवादित बयानबाजी करने वाले तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और एक बयान जारी करके मंत्रियों के बयानों को उनका निजी विचार करार दिया है और सरकारी रुख से अलग बताया है।

"रिवाइवल" प्रक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एफ.आई. की सार्वजनिक रैली में उसकी गत रैलियों की तुलना में स्पष्ट रुप से असमानता थी।

यह पहली बार था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) अर्थात माकपा की रैली के मंच के एक कोने में बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा था। माकपा अपने राजनैतिक क्रियाकलापों में भारत के राष्ट्रीय झण्डे को मान्यता देने से अब तक दृढ़तापूर्वक इन्कार करती रही थीं। हथौड़े और हंसिये वाला माकपा का लाल झंडा ही कार्यक्रमों में लहराता देखा जाता था।

वामपंथियों ने इस बार भारत के संविधान की कसम खाई, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। रैली की शुरुआत बंगाली राष्ट्रवाद के आव्हान के साथ हुई और उसका समापन भारत के संविधान की प्रस्तावना के पठन के साथ हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद का बयान एक तरह से वामपंथ के संदर्भ से परे था क्योंकि वामपंथी इससे पहले तक अन्तर्राष्ट्रीयवाद के कट्टर हिमायती रहे हैं।

अब कोई इस बात पर आश्चर्य कर सकता है कि चीन की विचारधारा और भारत से लगती सीमाओं पर उसके प्रति रहती आई अत्यधिक निर्भरता को लेकर वामपंथियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? "कम्युनिस्ट इन्टरनैशनल" के बिल्कुल विपरीत रैली की शुरुआत रवीन्द्रनाथ टैगोर के एक ऐसे गीत से हुई जिसे जीवन मूल्यों की आस्था के संदर्भ में गाया जाता था। टैगोर ने यह गीत 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में लिखा था।

वामपंथियों के दृष्टिकोण में कितना अंतर और परिवर्तन आ गया है, वामपंथी, जो पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर को बुर्जुआवादी का कवि मानते हुये, हमेशा तिरस्कार करते थे एवं उनसे दूरी बनाकर रखते थे। निजी तौर पर, सबके सब, निसन्देह ही बड़े उत्साह के साथ टैगोर के गीत गाते होंगे, जो कि बंगालियों के लिये एक आम बात है।

ज्यादातर इन गानों को अपने प्रियजनों के लिए उनसे मिलने की चाह या विरह के दुख में या फिर निराशा व उदासी में गाते हैं।

संयोग से, ममता बनर्जी ने उपरोक्त गीत को राजकीय गीत बना दिया है एवं राज्य विधानसभा ने हर सरकारी समारोह में इसका गाना अनिवार्य कर दिया है।

यह गीत आज के संदर्भ में एकदम सही नहीं है। यह गीत बहुत भावुक अपील और आशा करता है कि बंगाल वापस से एक हो जाये।

अक्षरश: इसका मतलब होगा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलकर एक हो जायें, इसके लिये या तो पश्चिम बंगाल, भारत से अलग होकर बांग्लादेश में मिल जाये या फिर बांग्लादेश भारत में सम्मिलित हो जाये और पुराना बंगाल वापस से बन जाये।

ये गीत चाहे एक स्वीकृत बंगाल की कामना करता है पर अपने होशोहवास में शायद ही कोई इस तरह की संभावना पर विचार करेगा।

यह गीत भगवान से प्रार्थना करता है कि बंगाल एक हो जाये। सार्वजनिक तौर पर वामपंथियों ने अब तक, भगवान का न तो जिक्र किया है न ही किसी कार्य को पूरा करने के लिये भगवान की मदद की कामना की है। पुराने वामपंथियों ने अपनी नास्तिक्ता और भगवान में अविश्वास, स्पष्ट रूप से जाहिर की है कम से कम सार्वजनिक रुप से वे ऐसा ही करते आए हैं।

रविवार की यह बैठक, परम्परागत सार्वजनिक वामपंथी बैठकों से बहुत अलग थी क्योंकि अभी तक, किसी मीटिंग में कभी भी किसी एक व्यक्ति को प्रोजैक्ट नहीं किया था और सबका महत्व बराबर है, यही संदेश हुआ करता था।

पर इस बार मीनाक्षी मुखर्जी, एक युवा चेहरा, ही पूरी कार्यवाही के केन्द्र में थीं। उन्होंने ही कार्यवाही का संचालन किया और उनको वामपंथियों की "रिवाइवल" करने की प्रक्रिया का "कैप्टन" घोषित किया गया।

पहली बार मंच पर कोई भी 60 साल से ज्यादा आयु का नेता नहीं था। वे सभी प्रथम पंक्ति में बैठे थे, मंच पर नहीं। अपवाद के रूप में, एक वृद्ध नेता मोहम्मद सलीम मंच पर थे, सिर्फ पूर्व महासचिव डी.वाई.एफ.आई. की हैसियत से। निश्चित रुप से यह युवाओं का मंच था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीटों पर वार्ता ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई चर्चा में प्रमुख मुद्दा इस बात पर केन्द्रित रहा कि हम राजधानी में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार करेंगे और विशेष रूप से उस स्थिति में जब कोई भी पक्ष कमज़ोर पड़ रहा हो।

कांग्रेसी नेता ने बताया कि "हमने आपको यह सुझाव दिया है कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य से दोनों पार्टियों का एक साझा सचिवालय बनाया जाए। ऐसा करने से न केवल दोनों दलों के मध्य सहयोग करने का सही संकेत जाएगा बल्कि हमारे नेताओं में भी सहयोग का संदेश प्रचारित होगा।"

हालांकि, उक्त बैठक में मौजूद एक कांग्रेसी ने इस बीच संकेत दिया और कहा कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई। नेता ने यह भी कहा कि "उन्होंने (आप पार्टी) जो सुझाव दिए हैं वे सकारात्मक हैं और उनके सुझावों पर जो हमने बाते पूछी हैं वे उसका जवाब हमें देंगे। आज की बैठक में जो नेता उपस्थित थे, सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि आप की बैठक में आप के जो नेता आए थे, उन्हें इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार नहीं था। यह बात उनकी ओर से हमें पहले ही बता दी गई थी।"

आज की बैठक, कांग्रेस और आर.जे.डी. के बीच बिहार में कल सम्पन्न हुई सीट बंटवारे को लेकर बैठक के एक दिन बाद हुई है वहां कांग्रेस ने महागठबंधन से लगभग दस सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांगी है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस 5-6 सीटें लेने को तैयार हो सकती है और जबकि वामपंथी पार्टी को अधिकतम दो सीटें मिल सकती हैं।

मंगलवार को सीटों के बंटवारे के लिए गठित कांग्रेस पैनल के सदस्य शिव सेना (यू.बी.टी.) एवं एन.सी.पी. के नेताओं से वार्ता करेंगे, इसमें कांग्रेस नेतागण अशोक चव्हाण, नाना पाटोले, पृथ्वीराज चव्हाण और वर्षा गायकवाड़ शामिल होंगे।

बैठक शुरु होने से पहले ही जे.डी. (यू.) के मुख्य प्रवक्ता के.सी. त्यागी ने कहा था कि उन्हें इंडिया गठबंधन की साझेदार पार्टियों के संगठनात्मक ढांचे को लेकर गहरी चिन्ता है क्योंकि उम्मीदवारों के चयन और पार्टियों की संयुक्तत जनसभाएं आयोजित करने के निर्णय और फैसले पर काफी विलम्ब हो गया है।

त्यागी ने यह भी कहा कि "कांग्रेस को केवल अपनी स्वयं की पार्टी की चिन्ता है जबकि हमें संपूर्ण इंडिया गठबंधन की है।"

आप पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति से चर्चा करने के लिए आप के महासचिव (संगठन) संदीप पाठक व दिल्ली की मंत्री आतिशी व सौरभ भारद्वाज को भेजा था। जबकि इस समिति में से वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश अधिकृत सदस्य हैं।

दोनों पार्टी के सदस्यों के मध्य लगभग दो घंटे चली चर्चा के बाद, वासनिक ने पत्रकारों-संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि "आई.एन.डी. आई.ए. गठबंधन की हम दोनों मजबूत और अति महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देखेंगे कि भाजपा को पराजित कर दिया है।"

वासनिक ने यह भी कहा कि हमने आगामी लोकसभा चुनावों में उठाए जाने वाले अनेक महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है।" वार्ता आगे भी चलती रहेगी और हम पुन: शीर्घ मिलेंगे और उसके बाद हम सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला करेंगे। बैठक में हर अहम् मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हम चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हम करारा जवाब देंगे।"

इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविन्द सिंह लवली भी उपस्थित थे, जबकि दिल्ली व पंजाब दोनों की कांग्रेस यूनिटें आप पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन करने के खिलाफ हैं आप की भी पंजाब यूनिट किसी भी प्रकार के ऐसे संबंध बनाने के पक्ष में नहीं है।

- **आप पार्टी दिल्ली में कुल सात सीटों में से चार पर दावा कर रही है और कांग्रेस को तीन ही सीटें देना चाहती है।**
- **कांग्रेस का मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में बना अलायंस पैनल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से बात कर चुका है और अब महाराष्ट्र में शिव सेना व एन.सी.पी. से बात की जाएगी।**

जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद सप्ताह भर में करीब 1,200 झटके दर्ज

टोक्यो, 08 जनवरी। जापान में इशिकावा प्रान्त के नोटो प्रायद्वीप में नववर्ष के पहले दिन आए शक्तिशाली भूकंप के बाद एक सप्ताह में करीब 1,214 झटके दर्ज किए गए हैं। एनएचके ब्रॉडकास्टर ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि, भूकंप के बाद के सप्ताह में तेज़ झटके आने के आसार हैं। भूकंप के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने और संचार बाधित होने की वजह से बचाव दल कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इन क्षेत्रों में नुकसान का आकलन भी नहीं हो सका है। इसी बीच, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस (32 से 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट) के ठंडे तापमान के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि हजार घरों की बिजली और पानी आपूर्ति ठप है।

ई.डी. को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माथुर ने दलील दी कि, याचिकार्ता को सिर्फ एक गवाह के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है।

निचली अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तेरह अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्